भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1563

26 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

विद्युतचालित वाहनों के उद्योग को प्रोत्साहन

1563. श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युतचालित वाहन (ईवी) उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्युतचालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने कि लिए कोई बैटरी स्वैपिंग नीति बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी हाँ। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम का चरण-II कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में कवर किया गया है जिसे 15 सितंबर,2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ख) और (ग): जी हां, नीति आयोग संबंधित पक्षों के साथ परामर्श से बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार कर रहा है।

*****